

Money muddle kills jobs in unorganised sector

FC BUREAU

New Delhi

MAJOR sectors of economy including FMCG, jewellery and SMEs have been hit by post demonetisation, while the unorganised sector is seeing job losses, said industry body Assocham.

Lamenting the lack of preparedness and the manner in which demonetisation was implemented, Assocham president Sunil Kanoria, in an interview to PTI, said perhaps the "gravity and the size of the challenge was not really understood".

Kanoria said, "There is a lot to be worked out for, the way it has been implemented I am sure even the prime minister is not happy," adding "It (demonetisa-



tion) will disturb the current scenario: It will have an impact on the GDP."

Sharing the ground-level scenario post the scrapping of Rs 500 and Rs 1,000

notes and the ensuing cash crunch, Kanoria said jewellery firms have been hit hard whereas the consumer goods area and small and medium enterprises have

also been impacted. "Some of the businesses, yes, Businesses which are directly linked to the consumer will get some impact", the Assocham president said, when asked whether the earnings of corporates will take a hit, at least in the ongoing and next quarter.

He pitched for "major tax reforms" for demonetisation to have the desired results in terms of checking black money and corruption, observing that the coming Budget "will be very, very crucial for this government". "They need to slash tax rates to such an extent that it does not allow or provides disincentives to people who create black money," Kanoria added.

Elaborating further, he said the Rs 2.5 lakh income

tax exemption threshold should be increased to Rs 5 lakh whereas between Rs 5 lakh and Rs 15-20 lakh the levy should 10 per cent so people do not feel the pinch. Kanoria said the average rate of Goods and Services Tax (GST) should be lowered to 15 per cent from 18 per cent.

On whether he sees job losses in the economy in the short to medium term, he said: "In unorganised (sector), which is the daily wage earner, there will be some impact at the moment... the sales will get affected so they (vendors) will not be able to pay on a daily basis. The small, unorganised sector of the economy will have some impact."

(With PTI inputs)

'Demonetisation hits jobs in informal sector'

NEW DELHI: The major sectors of the economy including FMCG, jewellery and SMEs have been hit post demonetisation while the unorganised sector is seeing job losses, according to industry body Assocham. In an interview to PTI, Assocham president Sunil Kanoria lamented the lack of preparedness and the manner in which demonetisation was implemented, saying perhaps the "gravity and the size of the challenge was not really understood." "There is a lot to be worked out for, the way it has been implemented, I am sure even the Prime Minister is not happy," Mr. Kanoria said.

असंगठित क्षेत्र में जा रही नौकरियां : एसोचैम

नई दिल्ली, प्रेटर : नोटबंदी के बाद एफएमसीजी, ज्वैलरी और छोटे-मझोले उपक्रमों (एसएमई) सहित अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। जबकि असंगठित क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो रहे हैं। यह कदम बिना समुचित तैयारी के उठाया गया। इसमें चुनौतियों का आकलन करने में बड़ी चूक हुई। यह बातें रविवार को उद्योग चैबर एसोचैम ने कही।

एसोचैम के अध्यक्ष सुनील कनोरिया ने नोटबंदी को लागू करने के तरीके पर अफसोस जाहिर किया। उनके मुताबिक इसकी गंभीरता और चुनौतियों का ठीक से आकलन नहीं किया जा सका। इसके लिए काफी काम किए जाने की जरूरत थी। जिस तरह से इसका क्रियान्वयन हुआ उससे शायद प्रधानमंत्री भी खुश नहीं होंगे। यह कदम मौजूद परिदृश्य को प्रभावित करेगा। इसका सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पर भी असर होगा। सरकार की ओर से 500 और 1000 के नोट बंद करने के बाद जमीनी हालात पर कनोरिया बोले कि ज्वैलरी फर्मों पर इसका सबसे ज्यादा असर हुआ है। कंज्यूमर गुड्स सेक्टर और छोटे व मझोले उद्यम भी इससे प्रभावित हुए हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या

- ◆ बिना तैयारी के किया गया क्रियान्वयन, चुनौती को आंकने में हुई चूक
- ◆ आभूषण कंपनियों पर इसका सबसे ज्यादा असर
- ◆ वांछित नतीजे हासिल करने को बड़े कर सुधारों की जरूरत



इससे वर्तमान और अगली तिमाही में कंपनियों की आमदनी प्रभावित होगी, कनोरिया ने कहा कि सीधे उपभोक्ताओं से जुड़े कुछ कारोबार पर निश्चित ही इसका असर होगा। एसोचैम के अध्यक्ष ने काले धन और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के मद्देनजर नोटबंदी के वांछित नतीजों को हासिल करने के लिए 'बड़े कर सुधारों' की वकालत की। उनके मुताबिक आगामी बजट सरकार के लिए काफी महत्वपूर्ण

लकी ड्रॉ से ई-पेमेंट को बढ़ावा देने की तैयारी नई दिल्ली : डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने अवार्ड स्कीम की सिफारिश की है। आयोग ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआइ को 125 करोड़ रुपये के सालाना बजट के साथ साप्ताहिक और तिमाही लकी ड्रॉ पुरस्कार योजनाओं की मदद से ज्यादा से ज्यादा लोगों को ई-पेमेंट के लिए प्रोत्साहित करने को कहा है। आठ नवंबर के बाद से किए गए सभी डिजिटल पेमेंट को लकी ड्रॉ में शामिल किए जाने की योजना है। इस संबंध में नीति आयोग जल्द ही विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर सकता है।

साबित होगा। कनोरिया ने कहा कि सरकार को टैक्स की दरें इस हद तक कम करनी होंगी जिससे काले धन का सृजन करने वाले हतोत्साहित हों। आयकर छूट की सीमा ढाई लाख रुपये से बढ़कर पांच लाख रुपये की जानी चाहिए। इसी तरह 15 से 20 लाख रुपये की आय पर 10 फीसद की दर से कर लगना चाहिए। वस्तु एवं सेवा कर की औसत दर को 18 से घटाकर 15 फीसद किया जाना चाहिए।

असर

एसोचैम ने कहा कि पांच सौ और हजार के नोट बंद करने के तरीके से सकल धरतू उत्पाद पर असर पड़ना तय है

नोटबंदी : असंगठित क्षेत्र में जाने लगीं नौकरियां

नई दिल्ली, 11 दिसंबर (भाषा)।

असंगठित क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ रही है। एफएमसीजी, आभूषण और लघु मशीनें उपक्रमों (एसएमई) जैसे अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र प्रभावित हुए हैं वहीं असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों की बड़ी संख्या में नौकरी चली गई है। उद्योग मंडल एसोचैम ने रविवार को यह बात कही।

एसोचैम के अध्यक्ष सुनील कनोडिया ने कहा कि नोटबंदी को बिना तैयारियों के लागू किया गया। संभवतः नोटबंदी के प्रभाव और चुनौतियों के बारे में ठीक से

- आभूषण कंपनियों पर नोटबंदी का सबसे अधिक असर हुआ है
- उपभोक्ता सामान क्षेत्र और लघु एवं मशीनें उद्योग भी इससे प्रभावित हुए हैं



समझ नहीं बनाई गई। कनोडिया ने कहा, 'इसके लिए काफी काम करने की जरूरत थी। जिस तरीके से इसे लागू किया गया है, मुझे भरोसा है कि प्रधानमंत्री भी

इससे खुश नहीं होंगे।' उन्होंने कहा कि नोटबंदी से मौजूदा परिदृश्य प्रभावित होगा। इसका सकल धरतू उत्पाद (जीडीपी) पर भी असर होगा।

सरकार द्वारा पांच सौ और एक हजार रूपए का नोट बंद करने के बाद से जमीनी हालात पर कनोडिया ने कहा कि आभूषण कंपनियों पर इसका सबसे अधिक असर हुआ है। उपभोक्ता सामान क्षेत्र और लघु एवं मशीनें उद्योग भी इससे प्रभावित हुए हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या इससे कर्मियों की आमदनी प्रभावित होगी, मौजूदा और अगली तिमाही में, कनोडिया ने कहा कि कुछ कारोबार जो सीधे उपभोक्ताओं से जुड़ा है निश्चित रूप से इससे प्रभावित होगा।

कनोडिया ने जोर देकर कहा है कि नोटबंदी के बाकी पेज 8 पर

बिना तैयारी के नोटबंदी

एसोचैम के अध्यक्ष सुनील कनोडिया ने कहा कि नोटबंदी को बिना तैयारियों के लागू किया गया। संभवतः नोटबंदी के प्रभाव और चुनौतियों के बारे में ठीक से समझ नहीं बनाई गई। कनोडिया ने कहा, 'इसके लिए काफी काम किए जाने की जरूरत थी। जिस तरीके से इसे लागू किया गया है, मुझे भरोसा है कि प्रधानमंत्री भी इससे खुश नहीं होंगे।' उन्होंने कहा कि नोटबंदी से मौजूदा परिदृश्य प्रभावित होगा। इसका सकल धरतू उत्पाद (जीडीपी) पर भी असर होगा।

नोटबंदी से छोटे उद्योग ठप, लोग हुए बेरोजगार

■ नई दिल्ली।

नोटबंदी से एफएमसीजी, आभूषण तथा लघु मझोले उपकरणों (एसएमई) जैसे अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र प्रभावित हुए हैं वहीं असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले बड़े संख्या में लोगों की नौकरी चली गई है। उद्योग मंडल एसोचैम ने यह बात कही।

एसोचैम कहा कि नोटबंदी को बिना तैयारियों के क्रियान्वित किया गया। संभवतः नोटबंदी के प्रभाव तथा चुनौतियों के बारे में ठीक से समझ नहीं बनाई गई। इसके लिए काफी काम किए जाने की जरूरत थी। जिस तरीके से इसे क्रियान्वित किया गया है मुझे भरोसा है कि प्रधानमंत्री भी इससे खुश नहीं होंगे। एसोचैम ने कहा कि नोटबंदी से



एसोचैम की रिपोर्ट

मौजूदा परिदृश्य प्रभावित होगा। इसका सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पर भी असर होगा। सरकार द्वारा 500 और 1,000 का नोट बंद करने के बाद से जमीनी हालात पर एसोचैम ने कहा कि आभूषण कंपनियों पर इसका सबसे अधिक असर हुआ है। उपभोक्ता सामान क्षेत्र और लघु एवं मझोले उद्योग भी इससे प्रभावित हुए हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या इससे कंपनियों

- बिना तैयारियों के लागू कर दी गई नोटबंदी
- एफएमसीजी, आभूषण क्षेत्र पर ज्यादा असर
- कर सुधार से ही मिलेंगे नोटबंदी के अच्छे नतीजे
- इसके लिए बजट में काफी कुछ करने की जरूरत
- पांच लाख तक की आय कर मुक्त करना जरूरी
- 20 लाख की आय पर हो सिर्फ 10% आयकर

की आमदनी प्रभावित होगी, मौजूदा और अगली तिमाही में, उद्योग संगठन ने कहा कि कुछ कारोबार जो सीधे उपभोक्ताओं से जुड़ा है निश्चित रूप से इससे प्रभावित होगा। एसोचैम ने जोर देकर कहा है कि नोटबंदी के वांछित नतीजे हासिल करने के लिए 'बड़े कर सुधारों' की जरूरत है। विशेषरूप से काले धन और भ्रष्टाचार पर अंकुश की दृष्टि से। उन्होंने कहा

कि आगामी बजट सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित होगा। कनोडिया ने कहा कि सरकार को आयकर की दरों को इस हद तक कम करना होगा जिससे काले धन का सृजन करने वाले लोगों को हतोत्साहित किया जा सके।

उन्होंने कहा कि आयकर छूट की सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कम से कम 5 लाख रुपए किया जाना चाहिए। इसी तरह 15 से

20 लाख रुपए की आय पर 10 प्रतिशत की दर से कर लगाना चाहिए। कनोडिया ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का औसत दर को 18 से 15 प्रतिशत किया जाना चाहिए। यह पूछे जाने पर कि क्या अर्थव्यवस्था में मध्यम अवधि में नौकरियों की कटौत होगी, उन्होंने कहा, 'असंगठित क्षेत्र जहां दैनिक आधार पर श्रमिकों का मजदूरी मिलती है उस पर फिलहाल कुछ असर पड़ेगा। बिक्री प्रभावित होगी जिससे वेडर दैनिक आधार पर भुगतान नहीं कर पाएंगे अर्थव्यवस्था का लघु, असंगठित क्षेत्र इससे प्रभावित होगा।' उन्होंने कहा कि संसद में गतिरोध अच्छा संकेत नहीं है। राजनीतिक दलों को अधिक परिपक्वता दिखाने की जरूरत है। ■ भाषा

